

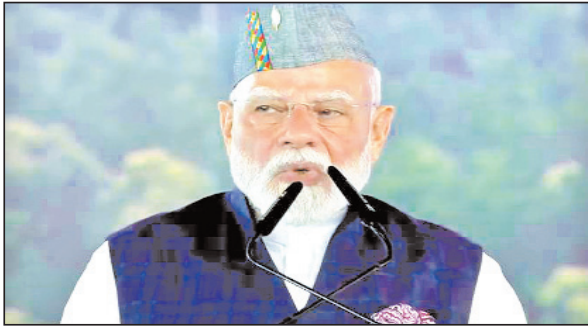
मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 344 बेमेतरा, सोमवार 10 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

मोदी ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ को स्मरण किया स्वतंत्रता सेनानियों के साहस की सराहना की

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके साहस और दृढ़ संकल्प को याद किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि इस आंदोलन में शामिल लोगों का बलिदान और संकल्प भारतीयों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को याद करता हूं। उनका साहस हमेशा हर



भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को याद करते हुए मोदी ने कहा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और

औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए हमारे लोगों के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। गौरतलब है कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ आठ अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पारित

होने के बाद शुरू किया गया था। इसी दौरान गांधी ने ‘करो या मरो’ का ऐतिहासिक नारा दिया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़े जन-आंदोलनों में से एक था। औपनिवेशिक अधिकारियों की कड़ी कार्रवाई के बावजूद, देश भर के लोगों ने विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और प्रतिरोध की गतिविधियों में हिस्सा लिया। आंदोलन शुरू होने के कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद, छात्रों, मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों की व्यापक

भागीदारी से यह आंदोलन जारी रहा। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की एक निर्णायक घटना बन गया और इसने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की बढ़ती मांग को स्पष्ट रूप से सामने रखा। दशकों तक चले राजनीतिक लामबंदी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आंदोलन के स्थायी महत्व और देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लोगों के साहस को रेखांकित किया।

असम बाढ़ प्रभावितों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी पांच करोड़ रुपये की सहायता

रायपुर। असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा की और मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी ली। सीएम साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि का उपयोग राहत और पुनर्वास कार्यों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और असम में जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की कामना की।



राजनाथ ने सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की, कहा रक्तदान को संस्कृति बनाए युवा

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के रक्षा बलों के अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन के साथ दुनिया को यह संदेश भी दिया कि देश अपने नागरिकों और महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सिंह ने दिल्ली छावनी स्थित बेस अस्पताल में ‘सिंदूर महारक्तदान यात्रा’ रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए सशस्त्र बलों द्वारा पकिस्तान स्थित आतंकवादियों और उनके आकाओं को समाप्त करने की सराहना की और कहा कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और रक्तदान



अभियान के बीच समानता बताते हुए सिंह ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने साहस का प्रदर्शन किया, वहीं इस मेगा शिविर ने करुणा का प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र के लगभग 1,000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने रक्तदाताओं के रूप में भाग लिया, जबकि शिविर में लगभग 500 स्वैच्छिक रक्तदाताओं

ने हिस्सा लिया। सिंह ने रक्तदान को जीवनदान और महादान बताया तथा जोर देकर कहा कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद मानव रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को एक संस्कृति बनाने का आग्रह किया और कहा कि रक्तदाता और रक्त लेने वाले अपने-अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से फिटनेस को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया और खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसी सरकारी पहलों का उल्लेख किया।

ईरान के साथ तनाव के बीच पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों से हथियार बनाने की रफ्तार बढ़ाने को कहा

मॉस्को। पेंटागन ने रक्षा कंपनियों से अमेरिकी सैनिकों के लिए हथियारों और गोला-बारूद के उत्पादन और आपूर्ति की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। ईरान के साथ तनाव की वजह से इनकी भारी कमी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आंतरिक दस्तावेज का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक 1,700 से भी कम रह गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, अमेरिका के उप रक्षा सचिव स्टीफन फीनबर्ग ने रक्षा अनुबंधकर्ताओं को हथियार आपूर्ति



की रफ्तार काफी बढ़ाने की योजना जमा करने के लिए 21 दिन का समय दिया है। अधिकारी ने ज़ोर देकर कहा कि सालों तक चलने वाले उत्पादन चक्र अब पेंटागन के लिए सही नहीं हैं। फीनबर्ग ने कई तरह के हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति को बहुत ज़रूरी बताया, जिनमें अगली पीढ़ी की एनजीआई इंटरसेप्टर मिसाइल,

एनएसएसएमएस वायु रक्षा प्रणाली, मोबाइल एयर डिफेंस रडार सिस्टम, एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग सिस्टम और स्पेस-बेस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। इससे पहले एनबीसी ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद-फोख़ा के लिए जिम्मेदार फीनबर्ग को व्यक्तिगत रूप से फोन करने के बाद, पेंटागन के अधिकारियों ने गोला-बारूद की कमी और सप्लाई से जुड़ी समस्या पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक 1,700 से भी कम है।

बृजमोहन-अमित कटारिया विवाद में पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी की एंट्री, बिरला से निष्पक्ष जांच की मांग

रायपुर। रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच चल रहे विवाद में अब मध्यप्रदेश की पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयश्री बनर्जी भी सामने आई हैं। बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर अमित कटारिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। बनर्जी ने 05 अगस्त 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अमित कटारिया के खिलाफ की गई शिकायत की जानकारी मिली। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई है। पूर्व सांसद ने अपने पत्र में 108



एंबुलेंस सेवा के टेंडर का मामला भी उठाया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के स्वास्थ्य विभाग में कार्यकाल के दौरान हुए 108 एंबुलेंस टेंडर में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। बनर्जी ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा सीधे आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं और इनकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष

ओम बिरला से सांसद अग्रवाल की शिकायत का संज्ञान लेने, स्वास्थ्य सचिव कटारिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने तथा जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार साबित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा के लिए मामले में उचित कदम उठाया जाना जरूरी है। अग्रवाल और कटारिया के बीच विवाद की शुरुआत 20 मई 2026 को हुई फोन पर

बातचीत के बाद होने की बात सामने आई है। सांसद अग्रवाल का आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने फोन पर उनसे कथित तौर पर कहा, जो करना है कर लो। अग्रवाल के अनुसार, जनहित से जुड़े उनके कई पत्रों और समूह पत्रों का लंबे समय से जवाब नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद 21 मई को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत भेजी। सांसद ने अधिकारी के कथित व्यवहार को सांसद के विशेषाधिकार और केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल से जोड़ते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की थी। मामले में आगे लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक मंत्रालय से तथ्यात्मक जानकारी मांगी। इसके बाद विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए।

आप सांसद संजय सिंह के ‘हाईजैक सरकार’ के बयान पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत

रायपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। गरियाबंद में आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी और केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद मीडिया से चर्चा में संजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारा जा रहा है और पेसा कानून का मजका उड़या जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज में सरकार को लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा, यहां के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन



अडानी और मोदी से आता है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार आज की तारीख में केंद्र सरकार के इशारे पर नाचने वाली सरकार है। पेपर लीक के मुद्दे पर आप सांसद ने कहा कि इस समस्या को लेकर पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2015 से लेकर अब तक 148 पेपर लीक हुए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड समेत भाजपा शासित राज्यों के मामले भी शामिल हैं। संजय सिंह

ने आरोप लगाया कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक में शामिल हैं। झारखंड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से वहां आरोप-प्रत्यारोप में मामला सही नहीं होगा। संजय सिंह ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र उनके पास आए थे और परीक्षा में सवाल गलत थे। उन्होंने कहा कि अब जो छात्र गलत आंसर दिया, वो सलेक्ट हो जाएगा और संबंधित बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि देश के हित के खिलाफ जो भी फैसला बीजेपी लेगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण हमने पास कर दिया।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया

तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आन, बान और शान: नड्डा

जयपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहा है कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान, शान और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2022 में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया। नड्डा ने रविवार को यहां तिरंगा रैली की संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसना चाहिए और इसके सम्मान एवं गौरव की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और मजबूत करने की दिशा में ‘प्रिंवेनस ऑफ़इंस्टिट्यूट्स टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026’ महत्वपूर्ण कदम है।



राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान भारत की शान हैं तथा इनके अपमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने देशवासियों से वीर सपूतों की कुर्बानियों से प्राप्त आजादी और तिरंगे की गरिमा को संदेव

के अभियान के रूप में नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना को सशक्त करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हर घर लहराता हुआ तिरंगा

राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। लेकिन यह सम्मान हमारे घरों के साथ ही हमारे दिलों में भी होना चाहिए। इसकी सार्थकता इसी में है कि हम राष्ट्रीय चेतना के आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में भी उतारें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाए जा रहा है। यह दिवस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर है। उनके त्याग और तपस्या के पत्तस्वरूप ही आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा संविधान के आदर्श, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। पहली

बार 15 अगस्त को फहराया गया तिरंगा राजस्थान में बना था। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के क्षणों का स्मरण करते हुए कहा कि उस समय विद्यार्थियों की टोली हाथों में तिरंगा था। ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा’ गीत के उद्घोष के साथ गलियों से गुजरती थी। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आतंकवाद और नक्सलवाद के खाले एवं दुनिया में भारत के बढ़ते गौरव तक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। आज का नया भारत दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई वर्षों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है।



शाह को पुडुचेरी से चेन्नई वापस ला रहा हेलीकॉप्टर मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण रविवार शाम चेन्नई हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका। इसके बाद करू ने हेलीकॉप्टर को तांबरम स्थिति भारतीय वायु सेना के एयरबेस पर सुरक्षित उतारा। तांबरम एयरबेस से गृह मंत्री अमित शाह लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करके सड़क मार्ग से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे, और फिर वे वहां से तमिलनाडु और पुडुचेरी की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी कर

नयी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री शनिवार शाम चेन्नई पहुंचे थे और वहां से हेलीकॉप्टर से तिरुवनं तपुर म/तिरुवन्नामलाई गए, जहां उन्होंने भगवान अरुणचलेश्वर मंदिर दर्शन किए और श्री रामन महर्षि आश्रम में प्रार्थना की। इसके बाद वे सड़क मार्ग से रात लगभग 8:30 बजे पुडुचेरी पहुंचे और लोक भवन में विश्राम किया। रविवार सुबह अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को ‘प्रेसिडेंशियल कलर्स’ (राष्ट्रपति का निशान) प्रदान किया।

संपादकीय

हाल के वर्षों में हवाई सफर की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। मगर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तकनीकी और सतर्कता के स्तर पर माकूल प्रबंधों का अभाव साफ नजर आता है। देश में हवाई यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए विमान सेवाओं से पुरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं। यदि बचपन स्वस्थ, संस्कारित, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। यदि बचपन ही अस्वस्थ, मोटापे, मधुमेह, कुपोषण और गलत खान-पान की आदतों से ग्रि्र जाए, तो विकास की पूरी अवधारणा खोखली सिद्ध होने लगती है। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

महाराष्ट्र सरकार का निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने यह स्वीकार किया है कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी राजनीतिक या आर्थिक हित से बड़ा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी राज्य इस दिशा में समान साहस और दूरदर्शिता दिखाएं। विकसित भारत की आधारशिला स्मार्ट शहर नहीं, बल्कि स्वस्थ बच्चे हैं। विकसित भारत का स्वप्न केवल आधुनिक इमारतों, तेज अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं से पुरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं। यदि बचपन स्वस्थ, संस्कारित, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। यदि बचपन ही अस्वस्थ, मोटापे, मधुमेह, कुपोषण और गलत खान-पान की आदतों से ग्रि्र जाए, तो विकास की पूरी अवधारणा खोखली सिद्ध होने लगती है। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों और उनके आसपास जंक फूड की बिक्री, वितरण तथा प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इसी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व का गंभीर संदेश है। यह स्वीकार करने का साहसिक प्रयास है कि बच्चों की सेहत बाजार के मुनाफे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। आज सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि बच्चे भोजन कम खा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे पोषण कम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक खा रहे हैं। रंग-बिरंगे पैकेट, आकर्षक विज्ञापन, कार्टून पात्रों की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया का प्रभाव और हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध फास्ट फूड ने बच्चों की स्वादेन्द्रियों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि घर का पौष्टिक भोजन उन्हें फीका लगने लगा है। यह परिवर्तन केवल खान-पान की आदत का बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे उनके शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध लगातार यह बताते रहे हैं कि अधिक वसा, अधिक नमक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ बच्चों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन तथा मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जो बीमारियां पहले चालीस-पचास वर्ष की आयु में दिखाई देती थीं, वे अब किशोरावस्था और बचपन में ही दस्तक देने लगी हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला संकट है। बचपन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वाद नहीं, पोषण है। शरीर के विकास के साथ-साथ मस्तिष्क का तीव्र विकास भी बचपन में ही होता है। यदि इस अवस्था में बच्चों को संतुलित भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होगा। इसके विपरीत जंक फूड क्षणिक स्वाद तो देता है, लेकिन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं देता। परिणामस्वरूप बच्चा बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु भीतर से अनेक पोषण संबंधी कमियों का शिकार बनने लगता है। दुर्भाग्य यह है कि जंक फूड आज केवल भोजन नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक व्यावसायिक संस्कृति बन चुका है। विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों के मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि आधुनिकता का अर्थ पैकेटबंद भोजन है। लोकप्रिय खिलाड़ी, फिल्मी कलाकार और डिजिटल प्रभावक अनजाने में बच्चों को

साथ ही विमान किराये में भी आए दिन बेलगाम तरीके से बढ़ोतरी होती रहती है। मगर इसी तर्ज पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है। कभी तकनीकी खराबी, सतर्कता की कमी, तो कभी मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां विमान हादसों का कारण बनती हैं।ऐसी ही एक घटना बीते मंगलवार को हुई, जब थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रहा एअर इंडिया का एक विमान वायुमंडलीय अस्थिरता यानी टर्बुलेंस के

कारण हवा में अपनी निर्धारित ऊंचाई से अचानक लगभग तीन सौ फुट नीचे आ गया, जिससे सत्रह यात्री घायल हो गए। हालाँकि, बाद में इस विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। सवाल है कि देश भर में होने वाले विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है? इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?यह सच है कि हाल के वर्षों में हवाई सफर

की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। मगर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तकनीकी और सतर्कता के स्तर पर माकूल प्रबंधों का अभाव साफ नजर आता है। पायलटों और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत के मुताबिक तैनाती नहीं हो पाने से संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है और इससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी अक्सर बनी रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार, करीब पैसंट

फ्रीसद विमान दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारण होती है। एअर इंडिया का जो विमान वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण असंतुलित हुआ, उसमें 137 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। अगर पायलट के समझने में थोड़ी सी भी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। फिर क्या वजह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मानक संचालन

प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पाया है?सवाल यह भी है कि इस घटना के दौरान खराब मौसम की स्थिति में संभावित वायुमंडलीय अस्थिरता के बारे में चालक दल की ओर से यात्रियों को पहले से सचेत करने की सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं? अगर यात्रियों को समय रहते सतर्क कर दिया जाए, तो विमान में मौजूद सुरक्षात्मक उपायों के इस्तेमाल से उनके हाताहत होने की संभावना कम होती है।

तेज रफ्तार जिंदगी में क्यों सबसे बड़ी ताकत बन गया है सब्र? हर दिन देता है इसका जवाब

(महिमा सामंत)

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्र की असली परीक्षा छोटे-छोटे पलों में होती है। सबसे आम उदाहरण है यातायात जाम। घर से निकलते ही यातायात जाम, दिन भर इंतजार और हर कदम पर अधीरता। आज की जिंदगी जैसे सब्र की लगातार परीक्षा बन गई है। तेज रफ्तार के इस दौर में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान। ऐसे समय में ‘सब्र’ शब्द भले पुराना लगे, पर सच यही है कि आज इसकी जरूरत पहले से कहीं अधिक है।

दरअसल, सब्र का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। यह उस इंतजार के दौरान अपने मन को संतुलित रखना है। यह वह समझ है, जो हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से रोकती है। जहां अधीरता क्षणिक राहत देती है, वहीं सब्र स्थायी सुकून देता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है और उस समय से पहले घबराना केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है।

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्र की असली परीक्षा छोटे-छोटे पलों में होती है। सबसे आम उदाहरण है यातायात जाम। जब हम किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं और रास्ते में लंबा जाम मिल जाता है, तो मन बेचैन हो उठता है। हम बार-बार घड़ी देखते हैं, हॉर्न की आवाजें हमें और चिड़चिड़ा बना देती हैं। मगर सच यही है कि उस जाम को हम तुरंत खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में जो व्यक्ति खुद को शांत रखता है, कोई साक्षात्कार सुन लेता है या बस गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है, वही मानसिक रूप से संतुलित रह पाता है। इसी तरह लंबी कतार में खड़े रहना, चाहे वह बैंक हो, अस्पताल हो या किसी दुकान की लाइन। कुछ लोग अधीर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बार-बार शिकायत करते हैं। वहीं कुछ लोग चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे व्यक्ति ने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। यही स्वीकार करना ही सब्र की शुरुआत है।

एक और साधारण लेकिन गहरा उदाहरण है ‘ट्रैफिक सिग्नल’ पर रुकना। लाल बत्ती होते ही कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। वे गाड़ी को थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कुछ पल पहले निकल जाना बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा। वहीं कुछ लोग उस रुकने को सहजता से स्वीकार करते हैं। सच यह है कि वह लाल बत्ती केवल सड़क का नियम नहीं, जीवन का संकेत भी है कि हर समय आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं। कभी-कभी

रुकना भी उतना ही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इस छोटे ठहराव को समझ लेता है, वह जीवन के बड़े ठहरावों को भी सहजता से पार कर लेता है।

आज के डिजिटल युग में भी सब्र की परीक्षा कम नहीं है। जब इंटरनेट धीमा हो जाता है या कोई फाइल लगातार परीक्षा बन गई है। तेज रफ्तार के इस दौर में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान। ऐसे समय में ‘सब्र’ शब्द भले पुराना लगे, पर सच यही है कि आज इसकी जरूरत पहले से कहीं अधिक है।

एक और आम स्थिति है - किसी के जवाब का इंतजार। हमने संदेश भेजा, फोन किया, लेकिन सामने से जवाब नहीं आया। मन तुरंत कई तरह के अनुमान लगाने लगता है। यही वह क्षण है, जहां सब्र की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम खुद को रोक लें और यह समझें कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में व्यस्त हो सकता है, तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं।

घर-परिवार में भी सब्र का महत्व बहुत बड़ा है। जब कोई बुजुर्ग किसी बात को बार-बार पूछते हैं या धीरे-धीरे काम करते हैं, तो हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा ठहरकर सोचें, तो समझ आएगा कि उन्हें हमारी जल्दी नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। ऐसे समय में दिखाया गया सब्र रिश्तों को गहराई देता है।

बच्चों के साथ व्यवहार भी सब्र का सबसे सच्चा आईना है। एक बच्चा जब नया कुछ सीखता है, तो वह बार-बार गलती करता है। अगर हम हर गलती पर गुस्सा करें, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, लेकिन अगर हम सब्र के साथ उसे समझाएं, तो वही बच्चा धीरे-धीरे बेहतर बनता है।

वैवाहिक जीवन में भी सब्र का भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। दो अलग-अलग स्वभाव, आदतें और सोच जब एक साथ आते हैं, तो मतभेद स्वाभाविक हैं। हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या अपनी बात मनवाने की जिद करना रिश्तों को कमजोर करता है। वहीं, अगर दोनों पक्ष थोड़ा ठहरकर एक-दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो वही मतभेद समझ में बदल सकते हैं। कई बार चुप रहना हार नहीं, बल्कि विश्वास का बचन है। रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि साथ निभाने की कला है।

पढ़ाई और करिअर के संदर्भ में देखें, तो आज हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है।

शिक्षा सुधार के दावे बहुत, बुनियादी बदलाव अब भी अधूरा-ऐसे नहीं बनेगा ज्ञान महाशक्ति भारत

(सुरेश सेठ)

यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है, तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। भारत शिक्षा के मामले में सदियों से अग्रणी रहा। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था दुनिया को राह दिखाती थी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। यहां गुरुकुल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। मगर समय बदलने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव हुए। भारत, जो कभी ज्ञान और नवजागरण के क्षेत्र में अग्रणी था, वह पिछड़ा चला गया।

हम पश्चिमी शिक्षा की नकल करने लगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शोध और अन्वेषण को कम कर दिया। कला संकाय का महत्व कम होता चला गया। शिक्षा पर बाजार हावी होने लगा। नए रास्ते पर चलने की हमारी ललक खत्म हो गई। दुनिया डिजिटल होती गई और इंटरनेट उसकी आधारभूमि बन गया। आज भारत कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है, तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे।

पिछले डेढ़ दशक में डिजिटल तकनीक को अपनाने और इस दिशा में आगे बढ़ने के कई दावे किए गए हैं। भारत कृत्रिम मेधा का अयुआ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कमी रह गई। यह कमी है संकल्प की। हम बेहतरीन शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। विद्वता बढ़ाने पर भी कोई जोर नहीं दिखाता। इच्छा और आकांक्षा जरूर थी, लेकिन अध्यापकों की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आया।

प्रवेश परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को भागीरथ प्रयास करने होंगे | पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर संबोधन कर आक्रोशित विद्यार्थियों को शांत करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है | इसमें उन्होंने प्रश्नपत्र लीक करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था की बात भी की | बीती 27 जुलाई को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ, तो परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया | इससे प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोहों पर नकेल कसी जा सकेगी |

विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करने को ही लक्ष्य मान बैठे। नतीजा यह कि मेहनत और अन्वेषण कर आगे जाने का उत्साह कम पड़ता चला गया। यही कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे पिछड़ती चली गई।

बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक भी इसलिए पिछड़े, क्योंकि उन्होंने खुद को अद्यतन नहीं किया। नतीजा यह कि हमारे विद्यार्थी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। डिजिटल में सहज होने के ऋम में हम कागज-किससे से दूर हो गए। इसी के साथ हम अपनी पुस्तक संस्कृति भी भूल गए। मोबाइल फोन पर ही कक्षाएं लगने लगीं। बच्चे भी वहीं पढ़ने लगे। किताबें कोने में धरी रह गईं। डिग्रियां पाने और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे रह गया।

प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से हो रही है। मगर जब बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बाहर आने लगे, तब इस समस्या को गंभीरता से लिया गया और यह मुद्दा बनने लगा। प्रश्नपत्र लीक को कुछ गिरोहों ने अपना धंधा बना लिया और वे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने लगे। वर्ष 2024

और 2026 में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक हुए। निराशा में डूबे कुछ विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले दिनों आंदोलन किया। युवा पीढ़ी का असंतोष आक्रोश में बदल गया। नतीजा, शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि, इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।

प्रवेश परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को भागीरथ प्रयास करने होंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर संबोधन कर आक्रोशित विद्यार्थियों को शांत करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है। इसमें उन्होंने प्रश्नपत्र लीक करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था की बात भी की। बीती 27 जुलाई को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ, तो परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया। इससे प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोहों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार इस विधेयक को काफी महत्व दे रही है, मगर इसमें गंभीर चिंतन नहीं दिखता है। इस पर संसद में व्यापक बहस भी नहीं हो पाई। कड़े दंड के प्रावधानों वाला यह विधेयक बहुमत के बल पर पारित तो हो गया, लेकिन परीक्षा व्यवस्था और

शिक्षा में सुधार के लिए यह काफी नहीं है।

पिछ्ला अनुभव बताता है कि दोषियों को सजा देने के कानून तो पहले भी थे। चाहे उनमें सजा इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी पिछले पच्चीस वर्षों में देश भर के अलग-अलग हिस्सों से जो प्रश्नपत्र लीक हुए और माफिया ने जो कारगुजारी की, उस हिसाब से बड़े पैमाने पर धर-पकड़ नहीं हुई।

फिलहाल सरकार ने एक बड़ी पहल की है। उसने त्वरित अदालतें बनाई हैं। तीन महीने में फैसला करके अपराधियों को कड़ी सजा देने की घोषणा भी की गई है, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में वकील के हाजिर न होने से अगली तारीख दे दी गई। दंड प्रक्रिया को चुस्त कर प्रवेश परीक्षाओं को शुक्तितापूर्ण तो बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यह पूरी तरह दोषरहित कैसे होगी? हालांकि, सरकार इसको लेकर गंभीर दिख रही है। उसने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यबल बना दिया है, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के काम की समीक्षा करेगा और प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए अपनी सिफारिशें देगा। इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। नीति-निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया आज

कितने आगे बढ़ चुकी है और हम अभी नारे ही गढ़ रहे हैं। हम नारे लगाते हैं डिजिटल भारत के हैं। हम बताते हैं कि भारत में मोबाइल क्रांति हो गई है और जल्द ही कृत्रिम मेधा को भी साध लिया जाएगा। इस दिशा में प्रगति निस्संदेह प्रशंसनीय है, मगर सवाल यह है कि क्या हम युवा पीढ़ी को नए रोजगार के काबिल बना रहे हैं? आज भी न तो अध्यापक और न ही छात्र नई राहों के अन्वेषी हैं। वे कोई नया शोध करना नहीं चाहते। वे बस डिग्रियां चाहते हैं। मगर सभी पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव नहीं होता। बरसों तक उन्हें वहीं पढ़ाया जाता है।

भारत की साठ फीसद आबादी गांवों में बसती है। मगर वहां पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, मोबाइल नेटवर्क या तो है ही नहीं या फिर बहुत कमजोर है और यहां चर्चा होती है कि नीट सहित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से ली जानी चाहिए। सुधार कैसे होगा, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका वही पुराना है? सरकार कहती है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि दसवीं तक पहुंचने के बाद उनमें से कई बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं।

उच्च स्तर पर शिक्षा में बदलाव का आधार स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। बदलाव करना है, तो प्राथमिक स्तर से हो। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, लेकिन यह सब रोजगार की गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, वह आश्वस्त हो कि उसकी मेहनत और डिग्री के मुताबिक उसे रोजगार अवश्य मिलेगा। इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। अध्यापकों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। नए माहौल के मुताबिक जब तक वे स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

